(he Lok Sabha in this respect, clarifying the Government's position in this matter, this House should also be taken into confidence.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मैडम, स्टेटमेंट तो...

उपसभापति: अभी यह तो होने दीजिए।

. **श्री सुंदर सिंह भंडारी** (राजस्थान): यह आज ही हो जाना चाहिए। फिर दो ही दिन बचे हैं।... (व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): कलकत्ता में आकर अपना बयान दिया। ...(व्यवधान)...

उपसभापति: अभी आपने कहा। वह खड़े हैं। आप चुप होंगे तभी वह बोलेंगे। वह बोल रहे हैं। बोलिए गुजराल जी।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL) Madam, I have taken note of your instructions. The needful will be done.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay? Now we go ahead with the Zero Hour submissions. Mr. Ajit P.K. Jogi.... He is absent.

SHRI R. MARGABANDU: Madam, i rise to make one point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, nothing.. ..*(Interruptions)*.. .Mr. Margabandu, no. Your name is Margabandu. So you are bound by that name! So please sit down and let me go according to the normal procedure. आप अपने मार्ग से बाहर मत निकलो। Don't go out of the decided way! Then we can finish the business. Help me! Yes, Shrimati Bharati Ray.

RE. NEGLECT OF EXCAVATIONS AT HARAPPAN SITES

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY (West Bengal): Madam, I rise to draw the attention of this august House to the utter neglect of historically significant excavations at Harappan sites.

As we all know, Madam, this spectacular civilization flourished over an extensive area covering, from the west, the Baluchistant hills and Makaran coast, to_ the east to Punjab and down west to northern Rajasthan and Gujarat. Madam, I was shocked to read a news item published by *The Hindustan Times* of 9th December, that at one site, Bhorgarh, in outer Delhi, the mound has been partly destroyed by ploughs, and at another place in Mandoli, part of the area is used for public toilets and part for a modern graveyard. In a third area, at Bhojpur, the mound is lying open and the trenches are filled with rainwater every monsoon.

Madam, these excavations are extremely significant because they have traced four successive cultural periods: The uppermost layer traces the mediaeval period, the second layer is connected with the Kushan era, the third with Indo-Arynas, and the last layer has found evidences of links with Harappan culture. As we all know, Madam, some western scholars, that is, orientalists, and some Indian shcolars, while constructing the ancient period of Indian history, focussed on the Orion age, the Vedic age. Some stressed the non-utilitarian aspect of the cultural history of India and some were concerned with the annals of dynasties and empires. But the corpus of evidence furnished by the Harappan culture indicates a new way of looking at our history.

Every civilization has its own virtues, but we can be truly proud of a civilization, a spectacular civilization—urban and sophisticated—that flourished in India in the third millennium B.C., long before the Aryans even set foot in this country. This needs further exploration. Its links with the Indo-Orion culture, so different from it and so late and far behind it, has I not yet been established.

We talk of heritage and history but we allow crucial evidences for constructing our past to be destroyed. I strongly urge upon the Government to preserve, develop, protect and explore the historically significant excavations at Harappan sites.

Thank you. i

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is a serious thing. Everybody supports it—there are no two opinions about it.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOT-RA (Delhi): We all associaie witn. it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We all associate. We are destroying our past without knowing it. We don't know about our past, really. We are destroying it ignorantly.

RE. NON-REPRESENTATION OF S.C/ S.T. IN PLANNING COMMISSION

श्री बंगारू लक्ष्मण (गुजरात): महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संयुक्त मोर्चा की नई सरकार के गठन के बाद योजना आयोग का पुनर्गठन हुआ है। इस योजना आयोग में लगभग 11 सदस्यों को लिया है। जैसा आप सब लोग जानते है कि योजना आयोग की शुरूआत 1950 में हुई है यद्यपि इस योजना आयोग के लिए कोई कानून नहीं है और न ही कोई संवैधानिक प्रोविजन है जिसके अन्तर्गत इसको अधिकार है। पिछले 45 साल का अनुभव यह बताता है कि योजना आयोग ने इस देश के विकास में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। जहां तक सबको मालूम है कि योजना आयोग जो आॅब्जेक्टिव्स और सोशल प्रोमिसेस बनाता है वह संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आधार पर बनाता है। इसीलिये यह सोचा गया पिछली बार जब-जब योजना आयोग बना था उस समय इस योजना आयोग के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रतिनिधि को उसमें रखा गया था। डा० स्वामीनाथन जनजाति के प्रतिनिधि के नाते से योजना आयोग में थे क्योंकि योजना आयोग जो स्टेट के एनुवेल प्लान्स होते हैं उनको क्लीयरेंस देता है। उसी प्रकार के सेन्ट्रल प्लान्स की क्लीयरेंस देता है, संयुक्त प्लान्स की क्लीयरेंस देता है। बिना योजना आयोग की क्लीयरेंस के कोई विकास का काम सम्भव नहीं है। पिछली छठी पंचवर्षीय योजना से एक बात शुरू हुई थी कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में उनके विकास पर खर्च होना चाहिये। उसी प्रकार से जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर ट्राइब्ल्स सब-प्लान की कल्पना की गई थी। तीन पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो गई, लेकिन अभी तक 50 प्रतिशत भी उन पर खर्च नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में सरकार अगर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रतिनिधि को योजना आयोग में नहीं रखती है तो यह क्या संकेत देता है एक तरफ तो आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं और आप यह कहते हैं कि हम उनको बराबर की भागीदारी देंगे, बराबरी देंगे हर बात में, लेकिन देखा यह जाता है कि आचरण में जब बात आती है तो मिनिमम प्रोग्राम में सारे गरीबों की बात करते हैं लेकिन गरीबों का एक भी प्रतिनिधि योजना आयोग में नहीं रखते हैं। इसका गलत मैसेज बाहर जायेगा। इसलिए सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि सरकार इस पर विचार करे और जो भी उनकी दृष्टि में योग्य प्रतिनिधि हो उसको निश्चितरूप से योजना आयोग का सदस्य बनाना चाहिये। क्योंकि हमारे सारे प्लान के पैसे में से कम से कम 25 प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेवलपमेंट पर लगाने की बात हमारे उद्देश्यों के अन्दर है। इस बात को ध्यान में रखकर उनके प्रतिनिधि को योजना आयोग में लाना आवश्यक है। इसके अलावा बाकी चीजों में भी सरकार उनकी भागीदारी की बात कर रही है लेकिन वहां पर भी उनकी भागीदारी नहीं हो पा रही है। आज अगर आप गवर्नरों की संख्या देखें तो इस देश के अंदर अनुसूचित जाति का कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसको गवर्नर के लिए लाया जा सकता था या वहां पर गवर्नर बनाया जा सकता था। आज हमारे 175 देशों के अंदर दूतावास हैं, राजदूत हैं और एम्बेसडर्स हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से कोई अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि मिलता है। ज्यूडिशियरी में भी कोई भागीदारी नहीं मिल रही है इसीलिए इस प्रकार की बातें आज खोखली लगती हैं। अगर सरकार इन बातों को झूठा साबित करना चाहती है तो तुरन्त योजना आयोग के अंदर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि शामिल करे।

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदया,...

उपसभापति: श्री हनुमनतप्पा जो भी बोलना चाहते हैं। वे एस०सी०/एस०टी० कमीशन के चेयरमैन हैं।

श्री गोविन्दराम मिरी: एक मिनट मैं एसोसियेट करना चाहता हूं।

उपसभापति: आप बोल दीजिए। यह ऐसा सबजक्ट है जिसकी कोई मुखालफत नहीं करेगा। आप भी बोलिएगा।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, the Ninth Plan is on the